committee which must go into it must be an independent body. How can a committee of the HAL look for defects in the people who are running it themselves? Half the people who are responsible for it are in this committee. Are they going to own up that they are responsible for it? I would like him to reply to my observations.

SHRI K. P. SINGH DEO: Sir, the hon. Member is very good at making a mountain out of a mole hill. I have not said that these are minor defects. The committee which went into it has said that these are minor defects. I am no expert like Mr. Suresh Kalmadi. But the experts in the committee—I hope he agrees that they are experts—I have been from the HAL, from the DGCA and from the Quality Control Board of the ASTE. As far as flight safety and other things are concerned, these are not connected with this. Now the present position is that the gliders which are flying have been flying for the last three months and there have been no accidents with them and we have received letters acclaiming these gliders and whatever has been brought out by the committee, these minor defects are being looked into. And as I said, in the next few days, the user, the producer and the designer are again meeting to resolve all these things.

SHRI SURESH KALMADI: Sir, on the question of flight safety, I would request you to direct the Government to ground these aircraft. It is very very dangerous for the raw cadets to fly them.

MR. CHAIRMAN: But you don't fly it.

SHRI SURESH KALMADI: I will definitely not fly this particular glider.

SHRIMATI RODA MISTRY: Since there is such a dispute between the Opposition and the Government Benches on the issue would the honourable Minister consider having a demonstration by HAL and Government for us to watch?

SHRI VISHWA BANDHU GUPTA: Sir, the Minister's reply is somewhat misleading. I was suggesting that the glider should be made for championship. My point was that the glider which is now being manufactured for training is unsatisfactory and it is incorrect to say that the users have given a clean chit to the aircraft. It is not so. The glider allotted to the Delhi Gliding Club has been grounded because some cracks have been found in the main operational area. Therefore, I suggest that the inquiry should be made now and it is not a question of grounding..

MR. CHAIRMAN: You have draw the attention of the honourable Minister and I am sure he will look into it.

SHRI K. P. SINGH DEO: I do not want the record to go like this. It is not a crack. It is a glue separation and I have said that the inquiry committee will look into it. They are meeting again in the next two or three days to resolve all these.

Shortage of Jute faced by Jute Mills

*322. SHRI INDRADEEP SINHA:
SHRI SURAJ PRASAD:†

Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that jute mills are facing shortage of jute and some of the mills are on the verge of closure as a result thereof;

(b) whether it is also a fact that the mills are demanding import of jute;

(c) what remedial measures are being contemplated; and

(d) what was the production of jute in 1982-83, 1983-84 and the anticipated production for 1984-85?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND IN THE DEPARTMENT OF SUPPLY (SHRI NIHAR RANJAN LASKAR): (a) to (d) A statement is laid on the Table of the House.

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Suraj Prasad.

Statement

(a) No mill has closed down on account of non-availability of raw-jute so far. In fact consumption of raw jute by mills during May and June, 1984 has been much higher than the consumption during the corresponding period of the previous year.

(b) Yes, Sir.

(c) To ensure equitable distribution of raw jute among the mills, and to help the weaker mills, the raw jute stock holdings of mills have been regulated under the Jute Control Order.

(d) The production of raw jute and mesta during 1982-83 and 1983-84 seasons is estimated at 63 and 66 lakh bales respectively. As regards production for 1984-85 season, firm estimates are not yet available. However, the sentative trade estimate is around 71—75 lakh bales.

श्री सूरज प्रसाद : इस क्वेश्चन के दरमियान सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है कि देश के अन्दर इसकी कमी है और इस जूट की कमी के जहां तक मेरी समझ है, तीन प्रांधान कारण हैं। एक तो यह कि सरकार जूट उत्पादकों को लाभप्रद कीमत नहीं देती है। दूसरा कारण यह है कि जो जूट खरीदने के लिये एजेंसी तैयार की गई है वह एजेंसी महज 10 से 20 लाख बेल्स जूट खरीदती है और तीसरा कारण यह है कि जूट उत्पादन में कमी, सरकार की अन्धाधुंध इनडिस्क्रीमिनेट जूट के आयात के कारण है। यद्यपि जूट की देश में कमी नहीं होती है लेकिन इन कारणों से जूट के उत्पादन में ठहराव आ गया है। जूट का उत्पादन महज 70-80 लाख बेल्स का ही होता है। गत दो साल में जैसा कि गवर्नमेंट ने स्वीकार किया है, 1982-83 और 1983-84 में 63 लाख तथा 66 लाख बेल्स का उत्पादन का अनुमान है जूट का उत्पादन किसानों को ठीक ढंग से कीमत न देने के कारण नहीं बढ़ रहा है। सरकार से मैं यह जानना चाहता हूं कि जूट इंडस्ट्री में संकट आ गया है जैसा कि सरकार ने स्वीकार किया है और क्वेश्चन नं० 2 में सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है कि जूट उद्योग के लोग जूट आयात के लिये मांग कर रहे हैं तो सरकार कितने जूट का आयात 1983-84 और 1984-85 में करने वाली है? दूसरी बात सरकार ने क्वेश्चन नं० "ग" के अंदर यह बात कही है कि जूट कंट्रोल आर्डर द्वारा उत्पादन को रेगुलेट करने के लिये कदम उठाया जा रहा है तो इस संबंध में जूट कंट्रोल आर्डर ने इसको रेगुलेट करने के लिये क्या कदम उठाया है?

SHRI NIHAR RANJAN LASKAR: Some of the things that the honourable Member has said are not based on facts. He said firstly that there is a crisis in the jute industry because of low production. Of course, in the last two-three years there was a little low production. But there was no crisis as such. I can quote the figures. For 1980-81 the production was 82 lakh bales; 1981-82 75 lakh bales; 1982-83 63 lakh bales; 1983-84 62 lakh bales of raw jute. In 1984-85, the current year we expect more, but because of the floods and rains according to the trade estimate it is about 72 to 75 lakh bales.

Against this, the consumption is 76 lakh bales in 1981-82; 79 lakh bales in 1982-83 and 67 lakh bales in 1983-84.

About imports and other things, much depends on the supply and demand position and only when it is necesary we go in for imports. The Hon'ble Member has asked for the figures of import. I will give the figures of import. In 1980-81 the import was 2 lakh bales; in 1981-82 it was NIL; in 1982-83 we imported 45,000 bales and in 1983-84 the import was 1.50 lakhs of bales. In

the current year it depends upon supply and demand position. Government is watching the situation and whenever necessary we take proper steps.

श्री सूरज प्रसाद : महोदय, सरकार ने यह कहा है कि 1982-83 में जो इम्पोर्ट हुआ है वह एक या दो लाख बेल्स का है। मेरे पास सरकार की एनुअल रिपोर्ट है। सन् 1982-83 की एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक 1982-83 में 6.7 लाख बेल्स जूट का इम्पोर्ट हुआ है। ये स्वयं स्वीकार करते हैं कि सन् 1981-82 में जूट का उत्पादन 75 या 76 लाख टन हुआ है। सन् 1981-82 में जूट का उत्पादन जब 75 या 76 लाख टन हुआ है और अगर कैरी ओवर भी 23-24 लाख बेल्स का है तो ऐसी स्थिति में मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि 1982-83 में आपने 6.9 लाख बेल्स मंगाये और प्राइसेज को डिप्रेस किया और जिसके कारण 1982-83 और 1983-84 में जूट का उत्पादन घटकर क्रमशः 63 और 86 लाख बेल्स का हो गया है तो मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि जूट का इम्पोर्ट करने की वजह से या प्राइसेज कम देने की वजह से सन् 1981-82 के दौरान जूट का जो उत्पादन हुआ, क्या सरकार ने उसमें जूट का प्राइस कम किया ? दूसरी बात मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जूट का इम्पोर्ट हुआ जिसके कारण जूट के उत्पादन में कमी आई है। इसलिये मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने जिस जूट का इम्पोर्ट किया उसका प्राइस क्या है, किस भाव पर सरकार ने बंगलादेश या थाईलैण्ड से जो जूट इम्पोर्ट किया, उसका प्राइस क्या है? तीसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि इस साल जो यह मांग हो रही है और यह मांग जूट बैरन्स की ओर से हो रही है कि जूट का इम्पोर्ट किया जाये क्योंकि जूट के उत्पादन में कमी आई है और उनका यह भी कहना है कि इस साल जूट का कंजम्पशन बढ़ गया है और 70 लाख बेल्स बहुत कम हैं, सरकार इस साल कितना इम्पोर्ट करने जा रही है? आप स्वयं भी यह कहते हैं कि मई और जून में जूट का कंजम्पशन बहुत बढ़ गया है, देश में जूट की कमी है तो मैं स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि इस साल सरकार कितना इम्पोर्ट करने जा रही है और इसका असर प्राइसेज पर किस प्रकार पड़ेगा ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मान्यवर, एक तथ्य माननीय सदस्य ने कहा कि सन् 1982-83 में छः लाख बेल्स का इम्पोर्ट हुआ। यह गलत है। सिर्फ 45 लाख बेल्स का इम्पोर्ट हुआ। मतलब यह कि आधे लाख से भी कम बेल्स का इम्पोर्ट हुआ था। सन् 1982-83 के आंकड़े आप देखें तो पता चलेगा कि उत्पादन 63 लाख बेल्स का और खपत मिलों में 75.5 लाख बेल्स की है और मिलों के अलावा चार लाख बेल्स की खपत हुई है। इस प्रकार से आप देखेंगे कि उत्पादन कम और खपत अधिक रही है। तब भी केवल 45 लाख बेल्स का आयात हुआ। उसी तरह की परिस्थिति सन् 1983-84 में भी रही। उत्पादन काफी कम रहा है और उसी दृष्टि से 6 लाख बेल्स का कोई सवाल ही नहीं है। केवल डेढ़ लाख बेल्स का आयात हुआ है और इसका प्रभाव, आयात का प्रभाव किसानों पर, जूट के दामों पर पड़ा कि नहीं तो अगर आप दामों को देखें तो दाम जो इधर रहे हैं वह सर्वाधिक रहे हैं गत वर्ष भी और इस वर्ष भी। यहां तक इसकी खरीद जुलाई में 694 रुपये प्रति क्विंटल रही जब कि इतना

दाम कभी नहीं रहा । इस वर्ष की भी अगर तुलना करें तो इससे सदन का समय जायेगा और सदन का बहुमूल्य समय मैं लेना नहीं चाहता हूं । लेकिन यह तथ्य है कि जूट के भाव सार्वाधिक रहे हैं और आयात का कोई भी प्रभाव किसानों पर नहीं पड़ा । बल्कि, इससे जो हमारे मजदूर बेकार होते हैं, मिलों में जो काम करते हैं तो इन दोनों के लाभ को देखते हुए यह किया गया है ।

श्री सूरज प्रसाद : इम्पोर्ट प्राइस कितना था यह आपने बताया नहीं ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : : ये आंकड़े इस समय मेरे पास नहीं हैं ।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : माननीय सभापति जी, जूट का उत्पादक बिहार और बंगाल है और जूट की अधिक खपत बंगाल में होता है । मिलें वहां अधिक हैं । जब जब जूट का बात आई माननीय मंत्री जी ने कहा कि 694 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से इन्होंने दाम दिये है । लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि यह दाम जो आपके हैं यह जूट कारपोरेशन के हिसाब से हैं विस्कोमान के हिसाब से हैं या किसानों को जो प्राप्त हुआ है उसके हिसाब से हैं ? हम वहां नजदीक के रहने वाले हैं और हमें पता है कि सरकार यहा पर दाम की घोषणा कर देती है खरीदने वालों का घोषणा करता है । लेकिन खरीदने वाले जाते किस समय पर हैं उनके समय पर न जान के कारण बिचौलिये कम दामों पर खरीदते हैं और फिर बिचौलिये उन्हीं दामों पर उसको बेच देते हैं जो दाम थे तय करते हैं । तो इसमें बिचौलिये खत्म हो, खरीदारी में विलम्ब न हो तो इसके लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ? दूसरी बात यह है कि किसानों को जूट की खेती करने के लिये वाणिज्य विभाग कौन सी सहुलियतें देना चाहता है कौन सी जानकारी देना चाहता है जिससे कि जूट की खेती बढ़े और जो आपको इम्पोर्ट, आयात करना पड़ता है वह न करना पड़े तथा किसान इस आयात की पूर्ति अपनी पैदावार से करे । इसके लिये किसानों को जानकारी और सुविधा आप क्या दे रहे हैं । सभापति महोदय, फिर मैं अंतिम बात को दोहराना चाहता हूं कि आपने 694 रुपये प्राइस बताई है तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस प्राइस के मुकाबले कितना अधिक प्राइस आपने विदेशों को दिया है ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : एक तो कम भाव जूट के लिये मिलने का जो बात माननीय सदस्य ने कही है जो उन्होंने चिन्ता व्यक्त की है यह बात सही है कि कुछ ऐसे स्थान जो इन्टीरियर में हैं, जो सड़कों से नहीं जुड़े है जहां पर अन्य साधन नहीं हैं भावों का उनमें फर्क रहता है । बिचौलिये उस परिस्थिति का लाभ उठाते हैं । यह हमारा दावा नहीं है कि शतप्रतिशत हर एक स्थान पर पूरी खरीद का प्रभाव है । लेकिन अगर आप देखें जूट कारपोरेशन ने जो खरीद की गत वर्ष तो बहुत तत्परता से की और उसका लाभ अधिकांश ग्रोवर्स को मिला है। जहां भी कमी है जो सुदूर जगह हैं उनको और भी सुदृढ़ लाभ पहुंच सके सुचारू रूप से उनका माल बिक सके इसके लिये हमारा सतत प्रयास है। जहां तक इस बात का प्रश्न है कि बाहर क्या भाव दिये, आयात के तो इस वर्ष अभी आयात हुआ ही नहीं इसलिये अभी इसका प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : सवाल गत वर्ष का है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : गत वर्ष के लिये मैंने कहा कि इस समय मेरे पास आंकड़े नहीं हैं। मैं आपके पास उन्हें प्रस्तुत कर दूंगा। लेकिन यह चीज

देखने की है कि अगर किसानों को भाव पूरे मिल रहे हैं तो भी अगर कच्चे माल की कमी की वजह से हमारे मजदूर इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो हैं, जो आर्गनाइज्ड सेक्टर में हैं, वह बेकार न हो जायें या मैटारियल की वजह से, अगर इस तरह की दिक्कत है तो उसको भी दूर करना हमारे लिये आवश्यक है।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : जूट का या मैटारियल में समझता हूं कि यदि आप बेराफाई करें तो इसकी कमी नहीं पड़ी है, बल्कि अधिक रहा है। आप इसका हिसाब लगा लें। कभी आप को आधा लाख टन और कभी डेढ़ लाख टन मंगाने की जरूरत पड़ता है। वह भी आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता इसकी है कि उसको प्राइस नहीं मिलता है उसको अनुदान नहीं देते हैं, आप किसानों को फेसिलिटाज की कोई बात नहीं करते हैं।

(Interruptions)

SHRI BHUBANESWAR KALITA: Sir, apart from raw jute some of the jute mills are facing closure due to financial difficulties. For example, the only jute mill in Assam at Silghat has already been closed due to financial difficulties faced by the management. On the other hand, looking into these difficulties, jute mills in prospective places like Kharupetia in Darrang District, which produces a large part of raw jute in Assam, are being delayed in establishment. Sir, my specific question before the hon. Minister is whether the Government is considering to give some financial assistance to these mills.

SHRI NIHAR RANJAN LASKAR: My young friend has suggested about the opening up of a new jute mill. Of course, this is not the question here. This is a different question. We will deal with that at some other time. Sir, the other one is a out the cooperative jute mill in Assam which is closed. We have examined the feasibility of this, and we have asked the State Government that if they like to revive this unit, they are welcome, and whatever necessary help is required will be given to them.

SHRI JAGESH DESAI: Will the hon. Minister be pleased to give the details of the Jute Licensing and Control Order and the effect of the Order on the availability of jute and its prices?

SHRI NIHAR RANJAN LASKAR: Sir, in order to correct the uneven distribution of raw jute among the different mills, the Jute Commissioner has issued orders under the Jute Licensing and Control Order, 1961, regulating the stock holdings of the mills, prohibiting the mills having large stocks to purchase additional quantities of raw jute. Sir, it is only in that direction to help small mills because big mills will not be able to go to the market and raw jute will be available to the small mills for purchase. This is one thing. Secondly, mills having large stocks are directed to bring down the stock-holding by a reasonable limit. Sir, at present, out of 63 mills which are functioning, 48 mills have stocks for below 4 weeks' consumption, while 5 mills have stocks for only 8 weeks, consumption and above. The balance 10 mills have stocks for between 4 and 8 weeks' consumption. This is the position.

MR. CHAIRMAN: Next question.

Violation of the Import Rules by M/s. Goyal Gases Private Ltd. Sahibabad, U.P.

*323. SHRI MUKHTIAR SINGH MALIK: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether Government have since completed the inquiry against M/s. Goyal Gases Private Ltd., Sahibabad, U.P., for violation of rules in the matter of import of Vaccum Tanks and Nitrogen Liquifiers;

(b) if so, what is outcome of the inquiry; and

(c) what action Government have taken against this Company on the basis of the inquiry report?